

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3457

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीप टेक स्टार्टअप्स

3457. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डीप टेक हब है और वर्ष 2023 के दौरान 480 नए उद्यम स्थापित किए गए हैं;
- (ख) वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 के दौरान डीप टेक स्टार्टअप्स के निधियन में 77 प्रतिशत की गिरावट के क्या कारण हैं और इस क्षेत्र के सामने आने वाली वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों के बारे में सरकार का विश्लेषण क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा वित्तपोषण की कमी को दूर करने और डीप टेक क्षेत्र में, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केन्द्रित स्टार्टअप्स के लिए सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से (ग) : देश में समावेशी और विविधतापूर्ण स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए, स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, डीपटेक जैसे विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ), दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप्स को एंटीटी के रूप में मान्यता दी जाती है।

31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 55 से अधिक उद्योगों के 1,52,139 एंटीटी को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से, 46,000 से अधिक एंटीटी को विविध प्रौद्योगिकी और संबंधित उद्योगों के रूप में मान्यता दी गई है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, और ऑगमेंटेड रिएलिटी / वर्चुअल रिएलिटी (एआर / वीआर) जैसे डीपटेक शामिल हैं।

सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) आदि प्रमुख स्कीमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के योग्य और मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, इन प्रमुख स्कीमों के माध्यम से, कुल 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता जुटाई गई है। विशेष रूप से, वर्ष 2022 और 2023 में, इन स्कीमों के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए कुल 6,300 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तपोषण जुटाया गया है।

उद्यम पूंजी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफएफएस शुरू की गई है। यह निधि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित की जाती है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। एफएफएस से सहायता प्राप्त एआईएफ के लिए एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना स्टार्टअप्स में निवेश करना अनिवार्य है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, एफएफएस से सहायता प्राप्त एआईएफ ने, स्टार्टअप्स में 20,572.14 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विशेष रूप से, वर्ष 2022 और 2023 में, एफएफएस से सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में 5,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इसमें से 3,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश एग्रीटेक, एआई, क्लीन टेक, ई-कॉमर्स, हेल्थ टेक और स्पेस टेक जैसे विविध प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के स्टार्टअप्स में किया गया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस को 01 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स के लिए 454.04 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। विशेष रूप से, वर्ष 2022 और 2023 में, चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स के लिए 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमें से विभिन्न प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों, जैसे एग्रीटेक, जैवप्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, क्लीन टेक, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स एप्लीकेशन के स्टार्टअप को 110 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुमोदित की गई है।

पात्र वित्त संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)] के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधकमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सीजीएसएस को लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और 01 अप्रैल 2023 से इसका संचालन शुरू किया गया है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप्स को 555.24 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी प्रदान की गई है। विशेष रूप से, वर्ष 2023 में, स्टार्टअप्स को 220 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी प्रदान की गई है, जिसमें से विविध प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों जैसे एयरोस्पेस और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), और जैव प्रौद्योगिकी आदि में स्टार्टअप्स को 60 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की गारंटी प्रदान की गई है।
